(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सितम्बर, 1992 से सितम्बर, 1993 तक आयकर (निगम कर सहित) और सीमाशुल्क के रूप में प्राप्त राशि क्रमशः 19649 करोड़ रुपये और 23845.38 करोड़ रुपये थी ।

(ख) 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की बकाया राशि क्रमशः 2083.06 करोड़ रुपये और 127.69 करोड़ रुपये थी ।

(ग) बजट अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

)करोड़ों रुपयों में)

	1992–93	1993–94
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	32080.90	33600.50
सीमा शुल्क	25211.65	27727.00
आयकर	15995	20000

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क राजस्व में कमी मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र और उद्योग में धीमी गति से वृद्धि होने के कारण हो सकती है ।

आयकर के संबंध में, सरकार राजस्व वसूलियों पर बराबर नजर रखे हुए है राजस्व वसूलियां बढाने के उद्देश्य से कर के बकायों को समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं । वसूलियां बढाने के लिए कर आधार को व्यापक बनाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

Intgrated rural Development Programme in Gujarat

498. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amount allocated to the Government of Gujarat under the Integrated Rural Development Programme during 1992-93 and during 1993-94 so far;

(b) whether the role and performance of the banks under the said schemes in Gujarat State have been reviewed; and

(c) the amount released and utilised so far and the number of families benefited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (c) Total allocation (Central and State) to Gujarat under Integrated Rural Development Programme is Rs. 20.10 crores and Rs. 30.90 crores during the year 1992-93 and 1993-94 respectively. Against this total release (Central & State) was Rs. 21.95 crores in 1992-93 and utilisation was Rs. 22.04 crores. During the current financial year (upto September, 1993) so far an amount of Rs. 23.93 crores have been released and the utilisation is Rs. 13.69 crores, benefiting 34031 families.

(b) A committee has been appointed by Reserve Bank of India to review all aspects of the implementation of Integrated Rural Development Programme including the role and performance of banks.

Loans to farmers in Gujarat

499. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of loan provide to the farmers by different nationalised banks in Gujarat State during the year 1992-93 and up to June in 1993;